Supply of SSK class submarines by M/s. Globtech International Corporation

2044. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Globtech International Corporation, owned by Admiral S. M. Nanda (Retired), has been entrusted with the supply of two SSK class submarines, manufactured by a West German firm; and

(b) whether the Ministry of Defence had submitted its own design to the West German firm for manufacture of these two SSK class submarines?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) No, Sir.

(b) The Naval Staff Requirements, drawn up by Naval Headquarters, were forwarded to M/s HDW of West Germany among others Consequently, M/s HDW had submitted a design which met the Naval Staff Requirements.

Transfer of senior physiotherapists in Military Hospitals

2045. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the maximum period for which Senior Physiotherapists in military hospitals are posted at one place;

(b) whether it is fact that senior phpsiotherapists at military hospitals at Delhi, Meerut, Agra, Ambala, Chandigarh and Jalandhar have been serving at their respective places of postings for long; if so, what are the details in this regard, stating the reasons therefor; and

(c) by when Government propose to effect tranesfers of those senior physiotherapists who have served for more than five years at one place?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PAIL): (a) There is no fixed tenure for Senior Phisio therapists in military hospitals.

(b) Currently, the posts of Senior Physiotherapists have not been authorised in military hospitals at Meerut, Agra and Ambala. These posts are authorised only at Delhi, Jalandhar and Chandigarh, of which the posts at Delhi and Jalandhar are vacant The Senior Physiotherapists at Chandigarh, stands posted since 16-10-1971.

(c) There is no turn-over policy for the post of Senior Physiotherapists for the present.

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्त

2046. श्री सत प्रकाश मालवीय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के अन्त में उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1987 में उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) 1984-85, 1985-86, 1986-87 के वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश राम) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमान, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें चक्र पर आधारित है, वर्ष 1983-84 के बारे में

उपलब्ध हैं। इन अनुमानों के अनुसार, 1983–84 में उत्तर प्रदेश में 530.6 लाख व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे थे। वर्ष 1986 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 10447 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जबकि इसकी तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 5850 करोड रुपये का था। उत्तर प्रदेश की वर्ष 1987–88 की वार्षिक योजना 2500 करोड़ रु० की निर्धारित की गई है, जो राज्य की 1989–87 की 2030 करोड रुपये की वार्षिक योजना से 23 प्रतिशत अधिक है। 1987–88 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये 268.76 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। योजना परिव्यय में जो वृद्धि की गई है, उसमें एस वृद्धि की ऊंची दर के लिये और कीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की गति को तेज करने की व्यवस्था है। इन कार्यक्रमों से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों और छोटे तथा सीमान्तिक किसानों की हालत में सुधार करने के उद्देश्य वाले अन्य कार्यक्रमों से बहुत बड़ी संख्या में गरीबों की गरीबी की रेखा को पार करने में सहायता मिलेगी।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमान पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित हैं। जिस अंतिम सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध है. वह 1983–84 में किया गया था। इसके बाद के वर्षों के संबंध में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए व्यक्तियों के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

2047. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986–87 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही :

(ख) पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा स्थिर मूल्यों (1970–71) पर तथा चालू मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान केवल वर्ष 1985–86 तक लगाया गया है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए)

	स्थिरांक मूल्य	चालू मूल्य
1983–84	575	1659
1984–85	580	1782
1985–86	587	1988

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये सभी क्षेत्रकों, जिनमें कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा तथा ग्राम व लघु उद्योग आदि शामिल है, में हर वर्ष अधिकाधिक निवेश किया जा रहा है। इन निवेशों से रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध हो रहे है। ये सभी प्रयास राज्य को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने में सहायक होंगे।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

2048. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों तथा उनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है और यह स्कूल कहां-कहां स्थित हैं; और